



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 192]	नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 10, 2019/आषाढ़ 19, 1941
No. 192]	NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 10, 2019/ASHADHA 19, 1941

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2019

मामला सं. (ओ. आई.) 08/2019

विषय : ईरान, मलेशिया, सिंगापुर चीनी ताईपेई, संयुक्त अरब अमीरात (यू ए ई) और संयुक्त राज्य अमरीका (यू एस ए) से विस्तार योग्य पॉलीस्टाइरीन के अतिरिक्त सभी प्रकार के पॉलीस्टाइरीन के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत।

फा. सं. 6/10/2019-डीजीटीआर.—मै. इनियोस स्टाइरोल्यूशन इंडिया लिमिटेड, बड़ोदरा और सुप्रीम पेट्रोकेम लिमिटेड, मुंबई (जिन्हें यहां इसके बाद याचिकाकर्ता या आवेदक भी कहा गया है), के साथ मिल कर ईरान, मलेशिया, सिंगापुर, चीनी ताईपेई, यू ए ई और यू एस ए (जिन्हें यहां संबद्ध देश भी कहा गया है) से "विस्तार योग्य पॉलीस्टाइरीन के अतिरिक्त सभी प्रकार के पॉलीस्टाइरीन" (जिन्हें यहां इसके बाद संबद्ध वस्तुएं अथवा विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) भी कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू करने के लिए समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे यहां अधिनियम भी कहा गया है) और समय समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण एवं क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे यहां इसके बाद नियमावली भी कहा गया है) के अनुसरण में निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे यहां इसके बाद प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है।

विचाराधीन उत्पाद

2. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद “विस्तार योग्य पॉलीस्टाइरीन के अतिरिक्त सभी प्रकार के पॉलीस्टाइरीन” हैं।
3. पॉलीस्टाइरीन विभिन्न उपभोक्ता उत्पादों के विनिर्माण में प्रयुक्त होने वाला एक परिवर्तनशील थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है। पॉलीस्टाइरीन को विभिन्न आकारों में ढाला जा सकता है, शीटों के निर्माण के लिए निकाला जा सकता है और फोम युक्त किया जा सकता है। इसके मुख्य प्रयोगों में रेफ्रीजरेटर्स और एयर कंडीनर्स, जैसे उपकरणों, स्टेशनरी, घरेलू वस्तुएं, एक्स्ट्रूडिड इंसुलेशन फोम, इलैक्ट्रिकल हाउसिंग, खिलौने और खाद्य पदार्थ संबंधी पैकिंग शामिल हैं। संबद्ध वस्तुओं को अध्याय 39 “प्लास्टिक और उसकी वस्तुएं” के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। छह अंकीय स्तर पर वस्तुओं को 390319 पर वर्गीकृत किया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और किसी भी प्रकार से उत्पाद के कार्यक्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

समान वस्तु

4. समान वस्तु के संबंध में नियम 2(घ) में निम्नानुसार व्यवस्था है :-
“समान वस्तु” से ऐसी वस्तु अभिप्रेत है जो भारत में पाटन के कारण जांच के अंतर्गत वस्तु के सभी प्रकार से समरूप या समान है अथवा ऐसी वस्तु के न होने पर अन्य वस्तु जो कि यद्यपि सभी प्रकार से समनुरूप नहीं है परंतु जांचाधीन वस्तुओं के अत्यधिक सदृश विशेषताएं रखती हैं;
5. याचिकाकर्ता ने कहा है कि याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएं और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तुएं समान वस्तु हैं। संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं और याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित वस्तुओं के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुएं और संबद्ध देशों से आयातित वस्तुएं अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं जैसे भौतिक और रसायनिक विशेषताएं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य एवं प्रयोग, उत्पाद विशिष्टताएं कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की शर्तों में तुलनीय हैं। प्रयोक्ता दोनों को प्रतिस्थापनीय रूप से प्रयोग कर सकते हैं और कर रहे हैं। दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए नियमों के अंतर्गत उन्हें “समान वस्तु” माना जाना चाहिए।
6. इसलिए, वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ, भारत में आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं को संबद्ध देशों से आयात की जा रही संबद्ध वस्तुओं पर लागू नियम 2(घ) के अर्थों के भीतर “समान वस्तु” के रूप में माना जा रहा है।

घरेलू उद्योग और आधार

7. आवेदक विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उत्पादकों के रूप में मै. इनियोस स्टाइरोल्यूशन इंडिया लिमिटेड, बड़ोदरा और सुप्रीम पेट्रोकेम लिमिटेड, मुंबई द्वारा दायर किया गया है। आवेदकों के अनुसार वे भारत में संबद्ध वस्तुओं के प्रमुख उत्पादक हैं जो भारत में कुल उत्पादन का 67 प्रतिशत उत्पादित करते हैं। आवेदकों ने सत्यापित किया है कि आवेदकों अथवा उसके किसी संबंधित पक्षकार द्वारा संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का कोई आयात नहीं किया गया है। आवेदकों के अतिरिक्त, भारत में संबद्ध वस्तुओं का केवल एक और अन्य उत्पादक है अर्थात् मै. एल जी पालीमर्स इंडिया प्रा. लि.।
8. अतः, प्राधिकारी ने निर्णय दिया है कि आवेदक, जो वर्तमान में कुल घरेलू उत्पादन के “प्रमुख समानुपात” को धारित करते हैं और नियमों के नियम 5(3) की शर्तों के भीतर सभी मापदंडों को भी पूरा करते हैं, नियम 2(ख) की शर्तों में एक पात्र घरेलू उद्योग का आधार हैं।

शामिल देश

9. वर्तमान जांच में शामिल देश ईरान, मलेशिया, सिंगापुर, चीनी ताइपेई, यू ए ई और यू एस ए हैं।

सामान्य मूल्य

10. आवेदक ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के सामान्य मूल्य का निर्धारण आईसीआईएस एलओआर द्वारा प्रकाशित पॉलीस्टाइरीन की प्रस्तुत कीमतों (जी पी पी एस और एच आई पी एस के लिए पृथक रूप से) के आधार पर किया है। चूंकि, प्रकाशित कीमतें दक्षिण पूर्वी एशिया के लिए हैं, इसलिए, आवेदकों ने सिंगापुर के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण करते हुए आई सी आई एस कीमतों में केवल पत्तन प्रभारों को जोड़ा है। इसके अतिरिक्त, ईरान, मलेशिया और यू ए ई में अभिभावी अनुमानित कीमतों को प्राप्त करने के लिए, आवेदकों ने सिंगापुर से क्रमशः ईरान, मलेशिया और यू ए ई को पत्तन प्रभार, बीमा और समुद्री माल भाड़ा प्रभारों को जोड़ा है। यू एस ए और चीनी ताइपेई के लिए आवेदकों ने आई टी सी व्यापार मैप के स्रोत से प्राप्त पॉलीस्टिरिन के आयात आंकड़ों का सहारा लिया है। चूंकि, ये संख्याएं सी आई एफ कीमतें हैं, आवेदक ने यू एस ए और चीनी ताइपेई में अदा किए गए अथवा अदायगी योग्य मूल्य के निर्धारण के लिए पत्तन प्रभारों और प्रयोज्य आधारभूत सीमाशुल्क को जोड़ा है। इसलिए, प्राधिकारी ने जांच शुरुआत के प्रयोजनार्थ, याचिकाकर्ता द्वारा यथानिर्धारित सामान्य मूल्य के साथ कार्रवाई को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया।

निर्यात कीमत

11. आवेदकों ने डी जी सी आई एंड एस, कोलकाता द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के आधार पर निर्यात कीमत का परिकलन किया है। कमीशन, समुद्री भाड़ा, पत्तन व्ययों, अंतर्देशीय माल भाड़े, समुद्री बीमा, ऋण लागत और बैंक प्रभारों के कारण कीमत समायोजन का दावा किया गया है। आवेदकों द्वारा दावा की गई निवल निर्यात कीमतों के संबंध में पर्याप्त प्रथम दृष्टया प्रमाण हैं।

पाटन मार्जिन

12. सामान्य मूल्य, और निर्यात कीमत की कारखानागत स्तर पर तुलना की गई है जो प्रथमदृष्टया संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के संबंध में उल्लेखनीय पाटन मार्जिन को दर्शाता है। इसके प्रथम दृष्टया प्रमाण हैं कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं का सामान्य मूल्य कारखानागत निर्यात कीमत की तुलना में अधिक है जो प्रथम दृष्टया दर्शाता है कि संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा भारत बाजार में संबद्ध वस्तु पाटित की जा रही हैं।

क्षति और कारणात्मक संबंध

13. आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना पर घरेलू उद्योग को क्षति के आकलन के लिए विचार किया गया है। आवेदकों ने कुल रूप में पाटित आयातों की बढ़ी हुई मात्रा के रूप में कथित पाटन के परिणामस्वरूप सामना की गई क्षति तथा भारत में उत्पादन और खपत, कीमत में कटौती, कम कीमत पर बिक्री, क्षमता उपयोग, लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। आवेदकों ने इसके अतिरिक्त, निवेदन किया है कि महत्वपूर्ण क्षति का जोखिम भी है। एक पाटनरोधी जांच की शुरुआत का औचित्य सिद्ध करने के लिए संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण उत्पन्न घरेलू उद्योग द्वारा सामना की जा रही "क्षति" के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं।

पाटनरोधी जांच की शुरुआत

14. और जबकि प्राधिकारी ने प्रथमदृष्टया यह पाया है कि पाटनरोधी जांच की शुरुआत का औचित्य सिद्ध करने के लिए संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति, उद्योग के क्षति एवं कथित पाटन और क्षति के बीच मौजूद कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य हैं, प्राधिकारी कथित पाटन की विद्यमानता, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की मात्रा की सिफारिश करने, जो यदि लागू होता तो घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होता, एतद्वारा नियमावली के नियम 5 की शर्तों में कथित पाटन और घरेलू उद्योग की परिणामी क्षति की जांच की शुरुआत करते हैं।

जांच की अवधि (पी ओ आई)

15. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 1 जनवरी, 2018 से 31 दिसंबर, 2018 (12 माह) है। तथापि, क्षति जांच अवधि में पिछले 3 वर्षों अर्थात् 1 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2016, 1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017, 1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 के आंकड़े तथा जांच की अवधि (पीओआई) शामिल हैं।

सूचना प्रस्तुत करना

16. संबद्ध देशों में निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकारों, भारत में संबद्ध वस्तु के आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे दिए गए पते पर पृथक रूप से निर्धारित समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं बताए गए तरीके से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने और प्राधिकारी को अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया गया है :

निर्दिष्ट प्राधिकारी
व्यापार उपचार महानिदेशालय
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
भारत सरकार

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5 संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001

17. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत कोई अनुरोध नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य पक्षों को उसे उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश भी प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

समय-सीमा

18. वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई के लिए कोई अनुरोध इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
19. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस जांच शुरुआत की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा पाटनरोधी उपायों को जारी रखने की जरूरत या अन्यथा के संबंध में घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें। सूचना मूल प्रतियों और सॉफ्ट प्रतियों में अवश्य प्रस्तुत की जानी चाहिए।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

20. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए उसके किसी भाग के संबंध में "गोपनीयता" का दावा करने के मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा:-

- i. गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि); और
- ii. अगोपनीय रूप में अंकित दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि)।

21. "गोपनीय" या "अगोपनीय" अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। दोनों पाठों की हार्ड कॉपियों के साथ साफ्ट कॉपियां चार (4) सैट में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

22. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
23. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।
24. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
25. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
26. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

27. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

असहयोग

28. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 10th July, 2019

Case No. (O.I.) 08/2019

Subject: Initiation of Anti-Dumping Investigation concerning imports of Polystyrene of all types except expandable Polystyrene from Iran, Malaysia, Singapore, Chinese Taipei, UAE and USA

F. No. 6/10/2019-DGTR.—M/s Ineos Styrolution India Limited, Vadodara along with Supreme Petrochem Ltd, Mumbai (hereinafter also referred to as the Petitioners or Applicants) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from

time to time (hereinafter also referred to as the Rules) for imposition of Anti-dumping duty on imports of "Polystyrene of all types except Expandable Polystyrene" (hereinafter also referred to as the subject goods or Product under consideration (PUC)) from Iran, Malaysia, Singapore, Chinese Taipei, UAE and USA (hereinafter also referred to as the subject countries).

Product under consideration

2. The product under consideration for the purpose of present investigation is "Polystyrene of all types except expandable Polystyrene".
3. Polystyrene is a versatile thermoplastic polymer used to manufacture various consumer products. Polystyrene can be moulded into various shapes, can be extruded to make sheets and can be foamed. The major applications include appliances such as Refrigerators and Air conditioners, stationary, household articles, extruded insulation foam, electrical housings, toys and food packaging. The subject goods are classified under chapter 39 "Plastics and Articles Thereof". At six-digit level, the goods are classified at 390319. It is also submitted that the customs classification is indicative only and in no way, it is binding upon the product scope.

Like Article

4. Rule 2(d) with regard to like article provides as under: -

"like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation;

5. The petitioner has submitted that subject goods produced by the petitioner company and the subject goods imported from the subject countries are like articles. There is no known difference between the subject goods exported from subject countries and that produced by the petitioner. Subject goods produced by the domestic industry and imported from subject countries are comparable in terms of essential product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers can use and are using the two interchangeably. The two are technically and commercially substitutable, and hence, should be treated as 'like article' under the Rules.
6. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the applicant in India are being treated as 'Like Article' within the meaning of the Rule 2 (d) to the subject goods being imported from the subject countries.

Domestic Industry & Standing

7. The Application has been filed by M/s Ineos Styrolution India Limited, Vadodara and Supreme Petrochem Limited, Mumbai as domestic producers of the product under consideration. According to the applicants, they are the major producers of the subject goods in India accounting 67% of the total production in India. The applicants have certified that there are no imports of the product under consideration by the applicants or any of its related party from the subject countries. Apart from the applicants, there is only one other producer of the subject goods in India, namely, M/s LG Polymers India Pvt. Ltd.
8. The Authority, therefore, determines that the applicants who presently hold a "major proportion" of the total domestic production, constitute an eligible domestic industry in terms of Rule 2 (b) and also satisfy the criteria of standing in terms of Rule 5 (3) of the Rules.

Countries involved

9. The countries involved in the present investigation are Iran, Malaysia, Singapore, Chinese Taipei, UAE and USA.

Normal Value

10. The applicant has constructed the normal value of the subject goods from the subject countries based on the spot prices of Polystyrene (separately for GPPS and HIPS) published by ICIS LOR. Since the published prices are for South East Asia, therefore, applicants have added only port charges in the ICIS prices for constructing the normal value for Singapore. Further, for arriving at the estimated prices prevailing in Iran, Malaysia and UAE, applicants have added port charges, insurance and ocean freight charges from Singapore to Iran, Malaysia and UAE respectively. For USA and Chinese Taipei, applicants have relied upon the import data of Polystyrene sourced from ITC Trade Map. Since these numbers are CIF prices, applicant have added port charges and applicable basic customs duty to make the value paid or payable in USA and Chinese Taipei. The Authority has, therefore, for the purpose of the initiation, decided to proceed with the normal value as constructed by the petitioner.

Export Price

11. The applicants have computed the export price on the basis of data published by DGCI&S, Kolkata. Price adjustments have been claimed on account of commission, ocean freight, port expenses, inland freight, marine insurance, credit cost and bank charges. There is sufficient prima facie evidence with regard to the net export prices claimed by the applicants.

Dumping Margin

12. The normal value and the export price have been compared at ex-factory level, which prima facie show significant dumping margin in respect of the subject goods from the subject countries. There is sufficient prima facie evidence that the normal value of the subject goods in the subject countries are higher than the ex-factory export price, indicating, prima facie, that the subject goods are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject countries.

Injury and Causal Link

13. Information furnished by the applicants has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The applicants have furnished evidence regarding the injury having taken place as a result of the alleged dumping in the form of increased volume of dumped imports in absolute terms and in relation to production and consumption in India, price undercutting, price underselling, capacity utilization, profitability, cash profits and return on capital employed. Applicants have further submitted that there is threat of material injury also. There is sufficient prima facie evidence of the 'injury' being suffered by the domestic industry caused by dumped imports from subject countries to justify initiation of an antidumping investigation.

Initiation of Anti-Dumping investigations

14. And whereas the Authority prima facie finds that sufficient evidence of dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject countries; injury to the domestic industry and causal link between the alleged dumping and injury exist to justify initiation of an anti-dumping investigation, the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of Rule 5 of the Rules, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which if levied, would be adequate to remove the 'injury' to the domestic industry.

Period of Investigation (POI)

15. The period of investigation for the purpose of present investigation is from 1st January 2018 to 31st December 2018 (12 months). However, the injury investigation period will cover the data of previous three years, i.e. 1st April 2015 to 31st March 2016, 1st April 2016 to 31st March-2017, 1st April 2017 to 31st March-2018 and POI.

Submission of Information

16. The exporters in the subject countries, their government through their Embassies in India, the importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

**The Designated Authority,
Directorate General of Trade Remedies,
Ministry of Commerce & Industry,
Department of Commerce Government of India
4th Floor, Jeevan Tara Building,
5, Parliament Street, New Delhi-110001**

17. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

Time Limit

18. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the AD Rules.
19. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application within forty days (40 days) from the date of publication of this Notification. The information must be submitted in hard copies as well as soft copies.

Submission of information on confidential basis

20. The parties making any submission (including Appendices/Annexure attached thereto), before the authority including questionnaire response, are required to file the same in two separate sets, in case "confidentiality" is claimed on any part thereof.
 - i. one set marked as Confidential (with title, number of pages, index, etc.), and
 - ii. the other set marked as Non-Confidential (with title, number of pages, index, etc.).
21. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions. Soft copies of both the versions will also be required to be submitted, along with the hard copies, in two (4) sets of each.
22. The confidential version shall contain all information, which is by nature confidential and/or other information, which the supplier of such information claims, as confidential. The information which is claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
23. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.
24. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
25. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
26. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of Public File

27. In terms of Rule 6(7) of the AD Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the information or evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

28. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. & Designated Authority